

Title: Need to take steps for the welfare of fishermen in Gujarat.

श्री नारनभाई काछडिया (अमरेली): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिलाना चाहूँगा। गुजरात राज्य में पाकिस्तान से सटी लगभग 1600 किलोमीटर की समुद्री सीमा है जो कि देश की सुरक्षा की नज़र से बेहद संवेदनशील और कमज़ोर है। इस लंबी समुद्री सीमा पर गुजरात राज्य के मछुआरों द्वारा प्रचुर मछली दल की खोज में जखाव जाना पड़ता है जो कि इंटरनेशनल मैरीन बॉर्डर लाईन (आई.एम.बी.एल.) के बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ पाकिस्तान मैरीन सिक्यूरिटी एजेंसी (पी.एस.एम.ए.) के लोग अक्सर भारतीय मछुआरों को उनकी बोट सहित पकड़ लेते हैं। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि सन् 1994-95 से लेकर 2011-12 तक पाकिस्तान ने 4529 मछुआरों को उनकी बोट सहित पकड़ा जिसमें पाकिस्तान ने अभी तक 4141 मछुआरों को छोड़ा है। इस प्रकार अभी 388 मछुआरे पाकिस्तान की विभिन्न जेलों में बंद हैं जबकि उनमें से कुछ मछुआरे 22 महीने से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं। वर्तमान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसके द्वारा मछुआरों को उसकी सज़ा काटने के बाद तुरंत रिहा किया जाए। इस संबंध में केन्द्र सरकार के साथ कई स्तर पर पत्र-व्यवहार और बैठकें की जा चुकी हैं। इसके अलावा सन् 2005 से पहले पाकिस्तान द्वारा पकड़े गए भारतीय मछुआरों को समुद्री रास्ते से बोट सहित छोड़ा जाता था, जबकि वर्तमान में पाकिस्तान पकड़े गए भारतीय मछुआरों को सड़क मार्ग द्वारा वाघा बॉर्डर के रास्ते छोड़ता है, तथा पकड़ी गई बोट को अपने स्थानीय मछुआरों को सस्ती कीमतों पर नीलाम कर देता है। इससे उन भारतीय मछुआरों के लिए उनकी आजीविका का कोई साधन नहीं बचता है। परिणामस्वरूप पकड़े जाने के बाद मछुआरों के सामने जीवनयापन करने की बड़ी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि स्वयं इस मामले में दृष्टिक्षेप करते हुए जनहित में गुजरात के मछुआरों की दशा में सुधार करने के लिए गंभीर से गंभीर कदम उठाएँ।